Daily Current Affairs
08 August 2026

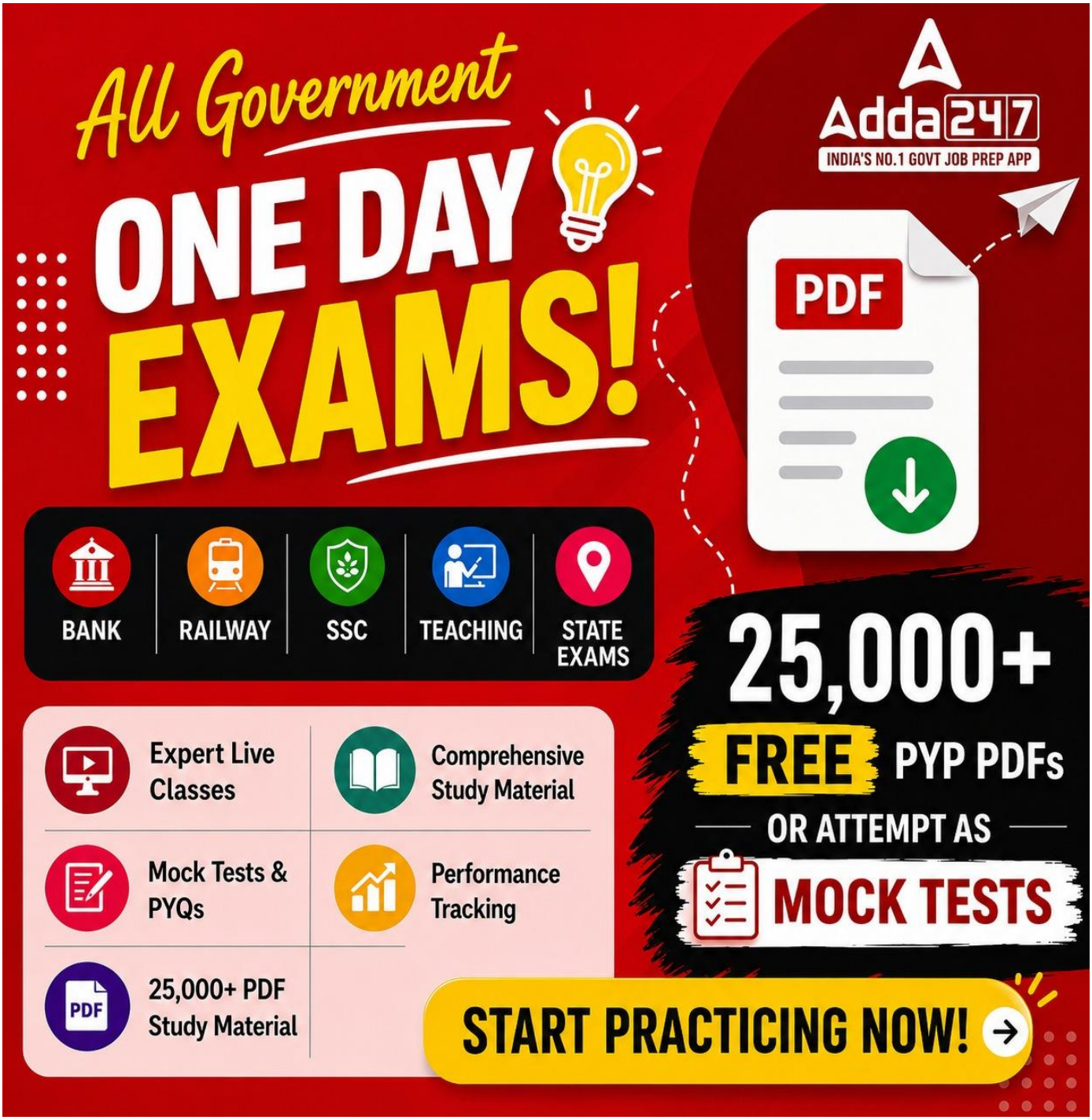

Daily Current Affairs Quiz 08 August 2026

Q1. 5 अगस्त 2026 को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत वापस लाए गए भगोड़े कितने देशों के थे?
(a) 42
(b) 28
(c) 36
(d) 50
Ans.(c)
Sol. सही उत्तर (C) 36 है
व्याख्या:
• ऑपरेशन त्रिशूल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा विदेशी अधिकार क्षेत्रों में छिपे हुए वांछित भगोड़ों और आर्थिक अपराधियों पर नजर रखने, उनका पता लगाने और उनके प्रत्यर्पण के लिए शुरू किया गया था।
• अगस्त 2026 में जारी आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए वापस लाए गए भगोड़ों को 36 अलग-अलग देशों से निर्वासित या प्रत्यर्पित किया गया था।
• यह अभियान बड़े वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराधों में शामिल व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए वास्तविक समय के खुफिया नेटवर्क, इंटरपोल रेड नोटिस और द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधियों का उपयोग करता है।
• यह अभियान भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सीमा पार पुलिस सहयोग और वैश्विक कानून प्रवर्तन एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़े प्रयास को दर्शाता है।
• इंटरपोल और समर्पित केंद्रीय एजेंसियों जैसे अंतरराष्ट्रीय चैनलों के माध्यम से रणनीतिक समन्वय ने भारतीय कानून से भागने वाले वैश्विक भगोड़ों के लिए सुरक्षित पनाहगाह के विकल्पों को काफी कम कर दिया है।
Information Booster:
• ऑपरेशन त्रिशूल वित्तीय सुरागों का मानचित्रण करके, खुफिया जानकारी का उपयोग करके विदेशों में संदिग्धों का भौगोलिक पता लगाकर और इंटरपोल नोटिस जारी करके काम करता है।
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-नई दिल्ली) के रूप में कार्य करता है।
• इंटरपोल मानक रंग-कोडित नोटिस जारी करता है, जिसमें रेड नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्रत्यर्पण लंबित रहने तक किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने के अनुरोध के रूप में कार्य करता है।
• इस अभियान के तहत वापस लाए गए भगोड़ों में साइबर अपराध नेटवर्क, बैंकिंग घोटालों, संगठित सिंडिकेट अपराधों और आतंकवाद से संबंधित अपराधों में शामिल व्यक्ति शामिल हैं।
Additional Knowledge:
• विकल्प A (42): गलत गणना। हालांकि भारत 40 से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधियां और व्यवस्थाएं बनाए रखता है, लेकिन ऑपरेशन त्रिशूल के आंकड़ों के तहत मूल देशों की विशिष्ट संख्या 36 है।
• विकल्प B (28): गलत संख्या। 28 भारत में राज्यों की कुल संख्या को संदर्भित करता है, न कि ऑपरेशन त्रिशूल प्रत्यर्पण डेटा में शामिल विदेशी देशों को।
• विकल्प D (50): गलत आंकड़ा। यह एक अनुमानित आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है और गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों से मेल नहीं खाता है।

Q2. भगोड़ों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय समन्वय के लिए किस संस्थान ने विशेष 'ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर' (Global Operations Centre) की स्थापना की?
(a) राष्ट्रीय जांच एजेंसी
(b) प्रवर्तन निदेशालय
(c) केंद्रीय जांच ब्यूरो
(d) इंटेलिजेंस ब्यूरो

Ans.(c)

Sol. सही उत्तर (C) केंद्रीय जांच ब्यूरो है

व्याख्या:

• केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर की स्थापना की।

• ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहायता और भगोड़ों की ट्रैकिंग को संभालने के लिए 24/7 चौबीसों घंटे कमांड यूनिट के रूप में कार्य करता है।

• यह राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय एजेंसियों और विदेशी समकक्षों को इंटरपोल नोटिस, प्रत्यर्पण कागजी कार्रवाई और पारस्परिक कानूनी सहायता अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करता है।

• यह केंद्र वैश्विक अपराध सिंडिकेट्स के खिलाफ ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन चक्र जैसे विशेष अभियानों को निष्पादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

• एक समर्पित संचालन केंद्र की स्थापना अंतरराष्ट्रीय अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर-सक्षम वित्तीय अपराधों से निपटने की भारत की क्षमता को आधुनिक बनाती है।

Information Booster:

• CBI की स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी और यह दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 से अपनी पुलिस शक्तियां प्राप्त करता है।

• CBI कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की प्रशासनिक देखरेख में कार्य करता है।

• ऑपरेशन चक्र FBI और इंटरपोल जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से CBI के नेतृत्व में एक प्रमुख साइबर अपराध विरोधी अभियान है।

• केंद्रीकृत समन्वय हब पूरे भारत में फील्ड पुलिस विभागों को वास्तविक समय की अंतरराष्ट्रीय खुफिया जानकारी तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।

Additional Knowledge:

• राष्ट्रीय जांच एजेंसी (विकल्प A): विशेष आतंकवाद निरोधी एजेंसी जो NIA अधिनियम, 2008 के तहत स्थापित की गई है, जो मुख्य रूप से आतंकवाद से संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करती है।

• प्रवर्तन निदेशालय (विकल्प B): राजस्व विभाग के तहत काम करने वाली वित्तीय जांच एजेंसी, जो PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) और FEMA लागू करती है।

• इंटेलिजेंस ब्यूरो (विकल्प D): भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी जो घरेलू जवाबी खुफिया, घरेलू सुरक्षा और आतंकवाद निरोधी निगरानी के लिए जिम्मेदार है।

Q3. 2019 से अगस्त 2026 तक, ऑपरेशन त्रिशूल के तहत कितने भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है?

(a) 274

(b) 174

(c) 370

(d) 245

Ans.(a)

Sol. सही उत्तर (A) 274 है

व्याख्या:

• अगस्त 2026 तक संकलित आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि ऑपरेशन त्रिशूल के तहत कुल 274 वांछित भगोड़ों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है।

• यह अभियान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), विदेश मंत्रालय (MEA) और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन निकायों के बीच निरंतर समन्वय के माध्यम से सफलतापूर्वक संचालित किया गया था।

• वापस लाए गए भगोड़े बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी और गंभीर हिंसक अपराधों सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे।
• उन्नत डिजिटल ट्रैकिंग, तेज रेड नोटिस प्रसंस्करण, और समर्पित वैश्विक संचालन इकाइयों ने इन प्रत्यावर्तनों की उच्च सफलता दर में योगदान दिया।
• वित्तीय और आपराधिक अपराधियों की व्यवस्थित वापसी सीमा पार कानून प्रवर्तन चुनौतियों से निपटने में भारत की बढ़ती क्षमता को उजागर करती है।
Information Booster:
• प्रत्यर्पण वह औपचारिक प्रक्रिया है जिसमें एक राज्य किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति को दूसरे राज्य को सौंपता है।
• भारत में प्रत्यर्पण 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम द्वारा शासित होता है।
• भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 भारतीय अधिकारियों को देश से भागने वाले वित्तीय अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है।
• ऑपरेशन त्रिशूल पुलिस बलों, आव्रजन अधिकारियों और अंतरराष्ट्रीय राजनयिक मिशनों को शामिल करते हुए सक्रिय अंतर-एजेंसी सहयोग को दर्शाता है।
Additional Knowledge:
• विकल्प B (174): 2025 से पहले अभियान के मध्य-चरण मूल्यांकन के दौरान दर्ज किए गए पूर्व के मील के पत्थर के आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है।
• विकल्प C (370): गलत संख्यात्मक मान। 370 व्यापक रूप से प्रत्यर्पण सांख्यिकीय डेटा के बजाय संविधान के अनुच्छेद 370 से जुड़ा है।
• विकल्प D (245): अगस्त 2026 में पूर्ण अद्यतन संसदीय गणना से पहले रिपोर्ट किए गए अनुमानित मध्यवर्ती आंकड़े का प्रतिनिधित्व करता है।

Q4. जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया कौन सा भारतीय प्लेटफॉर्म 1,400 से अधिक राज्य और केंद्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल से जोड़ने के लिए स्थापित किया गया था?
(a) अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS)
(b) NATGRID
(c) BHARATPOL
(d) I4C
Ans.(c)
Sol. सही उत्तर (C) BHARATPOL है
व्याख्या:
• BHARATPOL जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया एक समर्पित पोर्टल है जो पूरे भारत में 1,400 से अधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इंटरपोल के वैश्विक डेटाबेस से जोड़ता है।
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नेतृत्व में विकसित, BHARATPOL अंतरराष्ट्रीय अपराध खुफिया जानकारी के लिए सिंगल-विंडो इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है।
• यह तेजी से सीमा पार संचार, अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की ट्रैकिंग, विदेशी यात्रा दस्तावेजों के सत्यापन और इंटरपोल नोटिस जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।
• इंटरपोल पहुंच का विकेंद्रीकरण करके, राज्य पुलिस स्तर पर फील्ड अधिकारी वैश्विक आपराधिक डेटाबेस के खिलाफ संदिग्ध प्रोफाइल की तुरंत जांच कर सकते हैं।
• BHARATPOL भारत के पुलिस बुनियादी ढांचे को काफी आधुनिक बनाता है, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और मानव तस्करी के खिलाफ कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाता है।

Information Booster:
• CBI भारत में इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB-नई दिल्ली) के रूप में कार्य करता है।
• BHARATPOL इंटरपोल के सुरक्षित वैश्विक संचार नेटवर्क के साथ सहजता से एकीकृत होता है, जिसे I-24/7 के रूप में जाना जाता है।
• यह प्लेटफ़ॉर्म प्रत्यर्पण अनुरोधों को संसाधित करने और सीमाओं के पार चोरी की गई संपत्ति को ट्रैक करते समय प्रतिक्रिया समय को काफी तेज कर देता है।
• उन्नत तकनीकी एकीकरण वैश्विक पुलिसिंग पहल का समर्थन करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है।
Additional Knowledge:
• अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) (विकल्प A): पूरे भारत में पुलिस स्टेशनों को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय परियोजना जिसका उद्देश्य अपराधों और अपराधियों का एक व्यापक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है।
• NATGRID (विकल्प B): राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड; यह आतंकी संदिग्धों को ट्रैक करने के लिए सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को जोड़ने वाला एक एकीकृत खुफिया मास्टर डेटाबेस है।
• I4C (विकल्प D): भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र; देश भर में साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक पहल।

Q5. अगस्त 2026 में खबरों में रहा ऑपरेशन त्रिशूल मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(a) अंतरिक्ष अन्वेषण
(b) आपदा प्रबंधन
(c) भगोड़ों की ट्रैकिंग और प्रत्यर्पण
(d) साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण
Ans.(c)
Sol. सही उत्तर (C) भगोड़ों की ट्रैकिंग और प्रत्यर्पण है
व्याख्या:
• ऑपरेशन त्रिशूल केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नेतृत्व में एक विशेष राष्ट्रीय अभियान है जो विदेशों में छिपे आपराधिक भगोड़ों को लक्षित करता है।
• इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अदालतों में आपराधिक और वित्तीय आरोपों का सामना कर रहे वांछित अपराधियों का पता लगाना, उन्हें ट्रैक करना, वापस लाना और प्रत्यर्पित करना है।
• यह इंटरपोल चैनलों, अंतरराष्ट्रीय पुलिस नेटवर्क, विदेशी कानून प्रवर्तन साझेदारी और वैश्विक खुफिया साझाकरण का लाभ उठाता है।
• यह अभियान अंतरराष्ट्रीय अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने के लिए वित्तीय ट्रैकिंग के साथ आपराधिक डेटाबेस खुफिया जानकारी को जोड़ता है।
• ऑपरेशन त्रिशूल के माध्यम से, दर्जनों हाई-प्रोफाइल वित्तीय जालसाजों, आतंकवादियों और सिंडिकेट अपराधियों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया है।
Information Booster:
• CBI भारत में इंटरपोल का प्रतिनिधित्व करने वाले आधिकारिक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) के रूप में कार्य करता है, जो निर्बाध वैश्विक पुलिस समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।
• इंटरपोल विभिन्न नोटिस प्रदान करता है जैसे रेड नोटिस (भगोड़ों का पता लगाने/गिरफ्तार करने के लिए) और ब्लू नोटिस (किसी व्यक्ति की पहचान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए)।
• भारत ने विश्व स्तर पर द्विपक्षीय संधियों और पारस्परिक कानूनी सहायता समझौतों (MLATs) का विस्तार करके अपने प्रत्यर्पण नेटवर्क को मजबूत किया है।
• विशेष कानून प्रवर्तन पहल अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार कानून के शासन के सिद्धांतों को लागू करने में मदद करती है।

Additional Knowledge:

• अंतरिक्ष अन्वेषण (विकल्प A): ISRO के नेतृत्व में अंतरिक्ष अभियानों से जुड़ा है, जैसे गगनयान, चंद्रयान और आदित्य-L1 मिशन।

• आपदा प्रबंधन (विकल्प B): यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और सशस्त्र बलों जैसी एजेंसियों द्वारा चलाए गए आपातकालीन राहत कार्यों को संदर्भित करता है।

• साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण (विकल्प D): भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) और CERT-In के नेतृत्व में पहलों के तहत प्रबंधित किया जाता है।